

प्रेस रिलीज़

27 नवंबर 2019

नई दिल्ली

महाराष्ट्र की राजनीति से लोकतंत्र को हाईजैक करने की बीजेपी की साज़िश बेनकाब

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव एम. मोहम्मद अली जिन्ना ने आज मीडिया को जारी बयान में कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के बाद के राजनीतिक हालात ने सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जाने की बीजेपी की साज़िश को बेनकाब कर दिया है।

बीजेपी-शिवसेना गठबंधन टूटने के बाद सामने आए ड्रामाई घटनाक्रम, रातों-रात देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण और फिर फ्लोर टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री पद से उनका इस्तीफा यह सब स्पष्ट रूप से प्रदेश में आरएसएस के राज्यपाल, पीएमओ, अमित शाह यहां तक कि राष्ट्रपति की अनैतिकता का पता देते हैं। निसंदेह संविधान दिवस के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने उनकी सत्ता पर कब्जे की कोशिश को नाकाम कर दिया है। फडणवीस सरकार को फ्लोर टेस्ट का सामना करने का निर्देश देकर सुप्रीम कोर्ट ने न केवल बिना बहुमत के किसी दूसरे तरीके से सरकार बनाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए, बल्कि ऐसा करके अदालत ने संविधान की आत्मा को ज़िंदा रखा है।

फ्लोर टेस्ट से पहले ही सरकार गिरने पर, प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री अमित शाह को इस साज़िश में शामिल होने पर सफाई देनी होगी। महाराष्ट्र के राज्यपाल जो लोकतंत्र के साथ इस धोखे में बीजेपी का हथियार बने रहे, अब उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र पहला उदाहरण नहीं है जहां मोदी सरकार ने जनता की चाहत को हाईजैक करने की कोशिश की है और ऐसा भी पहली बार नहीं हुआ है कि न्यायपालिका ने उनकी गलत कार्रवाई को नेस्तनाबूद किया है।

दूसरी ओर मोहम्मद अली जिन्ना ने महाराष्ट्र में शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की गठबंधन सरकार के भविष्य और उसकी फितरत को लेकर चिंता व्यक्त की है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के साथ रहकर शिवसेना अधिक सेक्युलर होती है या कांग्रेस शिवसेना से प्रभावित होकर और ज़्यादा सॉफ्ट हिंदुत्व के रंग में रंगती है। उन्होंने यह विचार रखा कि महाराष्ट्र के राजनीतिक उथल-पुथल से उठने वाले सवाल का असल जवाब यह होगा कि प्रदेश में दलित मराठों और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिकता से खाली और बराबरी पर आधारित एकजुटता कायम हो।

डॉक्टर मोहम्मद शमून

डायरेक्टर, जनसंपर्क

मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया

नई दिल्ली